दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण पर नीतिगत निर्णय

5533. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के निराशाजनक कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनेकों बार नीतिगत निर्णय किये गये है,

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संस्थान के संबंध में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ये निर्णय किस-किस तारीख को लिये गये,

(ग) मार्च, 1994 तक क्रियान्वित किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान के कार्यकरण में सुधार के लिए अब तक किये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में हुए विलंब के कारण दिल्ली के आम बिजली उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ रही है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वयन में किये गये विलंब के क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) डेसू के कार्यकरण को सुधारने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य नीतिपरक निर्णय लिए गए हैं :—

(1) दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में बवाना में 400/450 मेo वाo गैस टरबाईन परियोजना की प्रतिष्ठापना (दिसम्बर, 1991)।

(2) दिल्ली नगर निगम से डेसू को विलग करने के लिए तथा डेसू को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत विद्युत बोर्ड में परिवर्तित करने के लिए (जुलाई, 1992)।

(3) दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण (मार्च, 1993)।

(4) डेसू की हानियों में कमी लाने के लिए विद्युत टैरिफ का संशोधन (1 अक्तूबर, 1993)।

(ग) से (ङ) बवाना परियोजना की स्थापना के लिए निजी पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन डेसू द्वारा किया जा रहा है ताकि अंतिम रूप से समुचित प्रस्ताव का चयन किया जा सके। दिल्ली नगर निगम की पुन:संरचना जिसमें डेसू को दिल्ली नगर निगम से विलग करना भी सम्मिलित है, के लिए आवश्यक विधेयक, 1993 में पारित किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में विद्युत वितरण निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए निजी पार्टियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं तथा विस्तृत बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावों की छटाई की जा रही है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से डेसू ने 1-10-1993 से अपनी टैरिफ में संशोधन किया है। दिल्ली में विद्युत वितरण के निजीकरण के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए तथा डेसू को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्युत यूटीलिटीज पर बढ़ी मात्रा में निर्भरता को देखते हुए सरकार डेसू की पुन:संरचना की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ताकि राजधानी में विद्युत आपूर्ति प्रणाली के लिए एक उपयुक्त तथा कुशल प्रबन्ध मुहैया करवाया जा सके। डेसू के पुनर्गठन पर किसी तरह का निर्णय लेते हुए आम उपभोक्ता के हितों के प्रति पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी।

Supply of High Voltage Direct Current Units

5534. **SHRI S.S. AHLUWALIA** : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Power Grid Corporation of India recently finalised a contract with a French Company for supply of high voltage direct current units in one of the first direct tie-ups with foreign investors;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether such units are available with BHEL, if so, what are the reasons for importing them from France?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (c) Powergrid Corporation of India has recently signed a contract for Chandrapur HVDC back-to-back (2×500 MW) project with the Consortium of British and French Companies. International competitive bids with financial package were invited for the Project. BHEL in collaboration with M/s. ABB Sweden also participated in the bidding. The Consortium's bid was the lowest.

Outlay for Power Generation in Gujarat

5535. **SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE** : Will the Minister of POWER be pleased to state :